मूल्य 1 रूपया

कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 64 | जुलाई, 2019 | अंक 7 | कुल पृष्ठ 8

सभापति का पत्र :

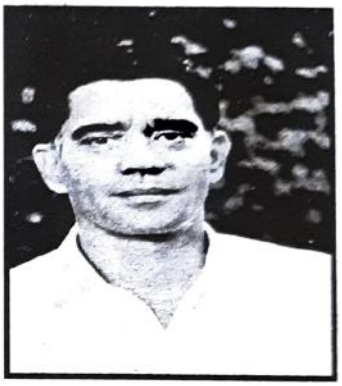

राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों में, दोनों का निरंतर जुनून वित्त अवसंरचना के लिए है, संभवतः राजनीतिक रूप से त्वरित विकास दिखाने के लिए, और संपत्ति निर्माण विभागों के अधिकारियों द्वारा संसाधनों के आसान निचोड़ के लिए भी अनुमति देता है। बजट की सबसे बड़ी प्राथमिकता मानव संसाधन विकसित करना होगा।

देश संघर्षशील खाद्य–प्रसंस्करण इकाइयों से भरा पड़ा है, जो अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और अपने ऋणों की सेवा करने में असमर्थ हैं। विभिन्न सब्सिडी योजनाओं के बावजूद, खाद्य–प्रसंस्करण की उम्मीदें अधूरी हैं। मामले की जड़ मांग पैदा करना था, लेकिन भारत फूड पाक्र जैसे बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहित करके आपूर्ति बनाने में निवेश कर रहा है। आधे से अधिक फूड पाक्र जिन्हें 50 करोड़ मिले, उनमें से प्रत्येक पहले ही बंद हो गया है और अधिकांश अन्य बंद होने के कगार पर हैं।

खाद्य–प्रसंस्करण जैसे डेयरी, आलू, टमाटर, जक्रिन आदि में कुछ सफलता की कहानियां मुख्य रूप से हो रही हैं, जहां किसान सीधे प्रोसेसर से जुड़े होते हैं। ऐसा एसलिए है क्योंकि प्रोसेसर एक विशिष्ट गुणवत्ता, ट्रैसेबिलिटी, वॉल्यूम चाहते हैं और इस तरह किसानों की कृषि विशेषज्ञता विकसित करने के पीछे निवेश करते हैं, उच्च मूल्य की पेशकश करते हैं, जो समृद्धि का एक अच्छा चक्र बनाता है।

प्रसंस्करण के लिए सबसे बड़ी बाधा विडंबना है कि पर्याप्त मात्रा में प्रसंस्कृत खाद्य किस्मों और फसल की कमी है। उदाहरण के लिए, आम की 100 से अधिक किस्में हो सकती हैं, लेकिन प्रसंस्करण के लिए केवल कुछ ही अच्छे हैं।

पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण कृषि अनुसंधान संस्थान फलों और सब्जियों पर शोध करने के बजाय प्रमुख फसलों पर केंद्रित रहते हैं। इससे पहले के दशक की तरह, पिछले 5 वर्षों में, कृषि अनुसंधान सरकार का सबसे उपेक्षित खंड रहा है। नतीजतन, आज पूरे भारत में कृषि अनुसंधान संस्थानों के स्वीकृत पदों में 50 प्रतिशत से अधिक रिक्तियां हैं और बजट में अंतर को भरना चाहिए।

इसके बाद, मांग उत्पन्न करने के लिए प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की एकमतता है। रेस्तरां और सेवा प्रदाताओं को अपने प्रसंस्कृत खाद्य खरीद के लिए इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता है। लेकिन यह काम जीएसटी परिषद के लिए कट ऑफ यूनियन बजट के दायरे से बाहर है। यह बेतुका है, जब सरकार का एक हिस्सा एक ऐसे क्षेत्र पर कर लगा रहा है जिसमें कोई और सब्सिडी दे रहा है। यह धान की बुआई की दक्षता बढ़ाने के लिए वित्त पोषण के औचित्य के लिए है, जबकि सरकार धान से दूर फसल विविधिकरण को लक्षित करती है।

– अजय वीर जाखड़

अध्यक्ष, भारत कृषक समाज

@ajayvirjakhar

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

पद्मश्री पुरस्कार 2019 जीतने वाले किसान

श्री नरेंद्र सिंह

मिलिए उस शख्स से, जिसने पशुओं की देखभाल करते–करते ऐसा काम कर दिया, जिसे आज तक कोई न कर पाया।

पानीपत जिले के इसराना में गांव डिडवाडी निवासी नरेंद्र सिंह द्वारा मुर्रा व साहीवाल नस्ल को संरक्षित करने पर सरकार ने इन्हें पद्मश्री अवॉर्ड दिया। नरेंद्र सिंह ने अमर उजाला को बताया कि बचपन से उन्हें पशुओं की देखभाल व लगाव का शौक था। उनका घर पर बीतने वाला ज्यादातर समय पशुओं की बेहतर ढंग से देखभाल करने में लगता था। वे किसान के साथ पंचायत विभाग में ग्राम सचिव भी थे। ड्यूटी के बाद पशुओं की देखभाल के समय यही प्रयास रहता था कि कुछ लीक से हट कर किया जाए। करीब 20 साल पहले नरेंद्र सिंह ने दस पशुओं के साथ गांव में अपने प्लॉट पर डेयरी की शुरूआत की थी। अब भैंस, झोटे व सांड़ समेत आज उनकी डेयरी फार्म पर करीब 150 पशु हैं। उन्हें वर्ष 2013 व 2015 में राष्ट्रीय अवॉर्ड, 2017 में गोपाल रत्न अवॉर्ड व वर्ष 2018 में मुर्रा रत्न अवॉर्ड से भी नवाजा जा चुका है।

विदेशी प्रतिनिधि भी आए थे पशुपालन तकनीक जानने को

मुर्रा नस्ल का झोटा घोलू, प्रिंस व शहंशाह समेत भैंसों की ख्याति देश भर के अलावा विदेशों में छाने के बाद करीब पांच वर्ष पहले उनकी डेयरी पर कोलंबिया के राजकुमार समेत कई देशों के प्रतिनिधियों ने विजिट कर पशुपालन की तकनीक को नजदीक से जाना था। उनकी डेयरी के हरियाणा साहिवाल सांड़ नंदी व मुर्रा नस्ल की भैंस प्रतियोगिताओं में प्रथम रह कर चैंपियन बनी व झोटा शहंशाह दूसरे स्थान पर रहा है।

पच्चीस करोड़ी शहंशाह रहा चर्चा में

पशुपालक नरेंद्र सिंह ने बताया की करीब 10 साल पहले उनके मुर्रा नस्ल के झोटे घोलू ने घूम मचाई थी, बाद में प्रिंस व अब शहंशाह चर्चा में है। नरेंद्र सिंह ने बताया कि उनके झोटे

शहंशाह को खरीदने के लिए देश के अलावा बाहर से भी लोग आए। कीमत पच्चीस करोड़ भी लगाई लेकिन उन्होंने बेचने से मना कर दिया। तभी से शहंशाह पच्चीस करोड़ी के नाम से चर्चा में है।

घाटे का काम नहीं है पशुपालन व्यवसाय

पशुपालक नरेंद्र सिंह ने बताया कि पशुपालन व्यवसाय को अगर बदलते समय की तकनीक के साथ अपडेट रह कर किया जाए तो पशुपालन कभी भी घाटे का सौदा साबित नहीं हो सकता।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

श्री सुल्तान सिंह

किसान सुल्तान सिंह ने गांव के तालाब को पट्टे पर लेकर मछली पालन का काम किया। उन्होंने उत्तर भारत की पहली मछली बीज हैचरी का निर्माण किया। उन्हें इस कार्य के लिऐ पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कई लोगों को मजबूरी से समझौता करते हुए देखा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन सब के बावजूद काबिलियत के दम पर मुकाम पाते हैं। एक ऐसे ही शख्स ने खेतीबाड़ी छोड़कर नई राह बनाई। आज वह खुद दूसरों को रोजगार दे रहे हैं, दूसरों के लिए प्रेरणादायी हैं।

गांव बुटाना के किसान सुल्तान को राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल चुका है। 1963 में गांव बुटाना में जन्मे सुल्तान को कई सालों तक मछली उत्पादन में देश का पहला रि–सर्कुलेशन एक्वाकल्चर सिस्टम लगाकर 1200 गज जमीन में 60 टन मछलियां पैदा कर रिकॉर्ड बनाने पर पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। यह पुरस्कार प्राप्त होने के बाद प्रदेश व जिले के किसानों के साथ–साथ समाजसेवियों में खुशी की लहर दौड़ गई।

500 रूपये से शुरू किया था कारोबार

सुल्तान सिंह के पारिवारिक सदस्य खेतीबाड़ी का काम करते हैं, लेकिन खेतीबाड़ी में ज्यादा मेहनत और कम मुनाफे से खफा होकर उन्होंने अपने मन में कुछ अलग करने की ठानी। बी. ऐ. की पढ़ाई करते हुए गांव के तालाब को 500 रूपये सालाना पट्टे पर लेकर मछली उत्पादन शुरू किया।

28 हजार लगाकर एक लाख 62 हजार कमाए

मछली उत्पादन में किसान सुल्तान सिंह ने अपनी मेहनत के बल पर 28 हजार रूपये की लागत लगाकर एक लाख 62 हजार रूपये का मुनाफा किया, जिसे देखकर किसान सुल्तान सिंह ने मत्स्य पालन करने का फैसला लिया। आसपास के गांवों के तालाबों को पट्टे पर लेकर मछली उत्पादन शुरू किया तो सफलता मिलती गई।

मछली बीज उत्पादन में महारत हासिल कर डैम भी पटटे पर लिया

इसके बाद वह कृषि विज्ञान केंद्र करनाल से जुड़े तो इन्हें डॉ. मारकंडे के नेतृत्व में मछली बीज उत्पादन की ट्रेनिंग मिली। फिर सुल्तान सिंह ने उत्तर भारत की पहली मछली बीज हैचरी का

निर्माण किया और हरियाणा के साथ–साथ अन्य राज्यों में बीज बेचने का कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद उन्होंने राजस्थान और महाराष्ट्र में डैम को भी पट्टे पर लिया और वहां भी मछली उत्पादन क्षेत्र में सफलता को चूमा। सुल्तान सिंह ने मछली उत्पादन क्षेत्र में नई–नई तकनीकों के साथ–साथ खोज का निर्माण किया। इसी के चलते किसान सुल्तान को राज्य–स्तर, राष्ट्रीय स्तर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई–कई बार सम्मान किया।

20–25 एकड़ की जगह आधे एकड़ में जमाया कारोबार

किसान सुल्तान सिंह ने बताया कि आधा एकड़ ऐरिया में 90 प्रतिशत पानी को रिसाइकल करके 60 टन मछली का उत्पादन किया, जोकि आम मछली पालक इतने टन मछली का उत्पादन 20–25 एकड़ भूमि पर करते हैं। उन्होंने बताया कि अब वह 3 करोड़ रूपये सालाना खर्च करके करीब डेढ़ करोड़ का शुद्ध लाभ प्राप्त करते हैं। वह भारत सरकार के साथ–साथ प्रदेश सरकार, जिला प्रशासन समेत गांववासियों का आभार जताते हैं, जिन्होंने मछली उत्पादन क्षेत्र में उनकी समय–समय पर हर संभव मदद की। उन्होंने पद्मश्री पुरस्कार मिलने का श्रेय अपने गुरू कृषि विज्ञान क़ेंद्र के हेड डॉ. मारकंडे, अपनी पत्नी संतोष देवी, बेटे नीरज व विपिन कुमार को दिया।

कई देशों के वैज्ञानिक ले चुके आधुनिक मशीनों का जायजा

किसान सुल्तान सिंह के बेटे नीरज ने बताया कि उनके गांव बुटाना स्थित मछली पालन फार्म में कई विदेशों के वैज्ञानिकों के साथ–साथ मछली पालक दौरा कर चुके हैं। यहां पर उन्होंने आधुनिक मशीनों के साथ–साथ किसान सुल्तान सिंह की ओर से विकसित तकनीकों का जायजा लिया। उनकी ओर से उजागर की गई कई–कई तकनीक विदेशी मछली पालक भी अपना रहे हैं। किसान नीरज ने बताया कि पिता सुल्तान सिंह को कई बार अंतर्राष्ट्रीय अवॉर्ड भी मिल चुका हैं और इजरायल, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाड़ा, इंग्लैंड़, चाईना समेत कई देशों में उनके मछली पालन व्यवसाय की गूंज है।

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

क्या संघर्ष के लिए तैयार हैं हम ?

* के.के. अग्रवाल

'खेती और किसान' पर भारी संकट है, आगे आने वाला समय किसानों के लिए चुनौतियों भरा है। किसानों को अब हर स्तर पर जद्दोजहद, संघर्ष के लिए तैयार रहना होगा। किसान अपना उत्पादन अब आसानी से सरकार को नहीं बेच पाएंगे। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह कुल उत्पादन का केवल 25 प्रतिशत ही खरीद पाएगी, शेष किसानों को जहां बेचना है, बेचें। यह जानकारी सरकार कई बार नीति आयोग व अन्य बैठकों में दे चुकी है, बैठकों में भाग लेकर लौटने के बाद हमने यह संदेश अपने किसान भाईयों को कई बार सांझा किया है, कोई नई बात नहीं है, सब जानते हैं, समझते हैं.....। न्यूनतम समर्थन मूल्य नोटिफिकेशन के तहत एक घोषणा मात्र है, जब तक इसका एक्ट (विधेयक) जो कि संसद में लंबित है, पारित

नहीं होगा, तब तक किसान लुटते ही रहेंगे। ....कोई भी वस्तु के दाम न्यूनतम कैसे हो सकते हैं ??, समझ के परे है।

किसानों को उसके उत्पादन की खरीद की गारंटी मिले, निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम दाम पर खुले बाजार में बिक्री पर सजा का प्रावधान हो ...जब तक यह नहीं होगा समर्थन मूल्य का लाभ किसानों को नहीं मिल पायेगा। इससे संबंधित एक्ट भी संसद में प्रस्तुत हो चुका है, पर जब सरकार की प्राथमिकता में किसान हैं ही नहीं, तो उस पर विचार संभव कैसे हो, कौन करेगा ??

फसलों की लागत, समर्थन मूल्य से ज्यादा है, यह सरकार भी मान चुकी है। इस संबंध में उन्हें आंकड़ों सहित विस्त्रित रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है। जब किसान की लागत ही नहीं निकलेगी, तो खेती लाभ का धंधा कैसे होगा ?

वर्ष 2006 में डॉ० स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया था कि कुल लागत, जिसमें जमीन का किराया, ब्याज आदि सभी शामिल हों (सी–2 फार्मूले के आधार पर) में 50 प्रतिशत लाभ जोड़ कर जब तक किसान को नहीं दिया जाएगा, किसान घाटे में ही रहेंगे। उनकी उन्नति संभव ही नहीं है। उन्होंने 15 अगस्त, 2007 से इसे लागू करने की शिफारिश की थी, 11 वर्ष बीत गए अभी तक लागू नहीं हो सकी, सरकारें किसी की भी रही हों, उनकी प्राथमिकता में किसान कभी रहा ही नहीं। इसका भी एक्ट संसद में विचारधीन ही है। विडम्बना है किसानों की ओर किसी को गंभीरता से सोचने की फुरस्त नहीं है। 2007 से यदि रिपोर्ट लागू हो जाती तो हम पर कर्ज का बोझ नहीं बढ़ता। कर्मचारियों के वेतन आयोग तो पूर्व वर्षों से एरियर्स दिलवाते हैं, पर किसानों के लिए कमीशन जिसे सरकार ने ही बनाया था को तबज्जों नहीं दी गई।

11 वर्षों में सरकार ने किसानों के साथ ज्यादती की और 10 लाख करोड़ से ज्यादा बचा लिए। हमसे बचाये गए पैसे से ही, हमारे किसान कर्ज से मुक्ति चाहते है, जो ज्यादा नहीं है, केवल 4 लाख करोड़ से कम है। हम खैरात नहीं मांग रहे, यह हमारा हक है। उद्योगों का तो 12 लाख करोड़ एन.पी.ऐ. हो सकता है, पर किसान का नहीं, ऐसा क्यों ? उस पर ही कहर क्यों ??

जब किसान को सरकार उचित मूल्य नहीं दे पर रही, तो उन्हें सब्सिडी, प्रोत्साहन, राहत, सेवाओं में प्राथमिकता, पैंशन क्यों नहीं, हमारी सरकार वैश्विक दबाव में क्यों ??, क्या विश्व के अन्य देश नहीं देते। मुझे इसके अध्ययन के लिऐ अमेरिका सहित कई देशों का भ्रमण करने का अवसर मिला, सभी देश अपने किसानों को भरपूर सब्सिडी देते हैं, फसलों को पूरा सुरक्षा कवच। हर तरह का बीमा। छोटे से लेकर बडी सभी मशीन सस्ते किराए पर। वे अपने किसानों की पूरी मदद करते हैं।

किसानों के लिए हमारे देश में ही बंदिशें क्यों ?? हमारे यहां फसल बीमा देखें तो वह भी आधा अधूरा। अव्यौहारिक। कोई सुधार करने को तैयार नहीं।

यह सब काम दृढ़ ईच्छा शक्ति के साथ सरकारों को मिलकर करना होगा, आखिर तेलंगाना सरकार अपने किसानों को आठ हजार प्रति एकड प्रति वर्ष दे ही रही है, उन्होंने अपनी बीमा

पॉलिसी बनाई। कैसे ? सबको सोचना होगा। इसके बिना किसान का पोषण, उनका जीवित रहना (सर्वाइवल) सम्भव नहीं होगा।

आश्चर्य तो यह है कि हम किसान 60 प्रतिशत में हैं, और हमारे लिए बजट मात्र कुल देश के बजट का 3 से 4 प्रतिशत ही, प्रान्त का बजट 6 से 7 प्रतिशत तक ही बस। इसी से पता चलता है कि हम सरकारों की कितनी प्राथमिकता में हैं। विडम्बना तो यह है कि इस मूल जड़ पर किसी का ध्यान नहीं है। किसी को कोई चिंता नहीं। कोई मांग नहीं, कोई दबाव नहीं। जब बजट ही ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा, तो हमारे कल्याण की कल्पना ही बेमानी है। देश की जी.डी.पी. में हमारी भी हिस्सेदारी एक तिहाई है, तो फिर हम कमतर क्यों ?? हमारा बजट कम से कम 25 प्रतिशत तो हो, यह हमरा हक है। इसके लिए हमे सबको मिलकर संघर्ष करना होगा।

सरकार को यह भी समझना होगा कि सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर 'कृषि' के सेक्टर में ही हैं। मशीनीकरण व ऑटोमेशन के चलते उद्योगों से रोजगार नहीं बढ़ सकेंगे। ऐसा नहीं है की सरकार को यह मालूम नहीं है, पर स्वार्थों के चलते उद्योगों से मोह टूटना असंभव ही लगता है। हमारे लिए कम बजट के चलते ही प्रदेश सरकारों को दिया जाने वाला खरीद का लक्ष्य भी निहित है (खरीद के लिए, भंडारण की व्यवस्था हेतु राशि ही नहीं है) ...और परिणाम ....ज्यादा खरीद पर, उत्पादन का उठाव करने व भुगतान से इनकार। कम खरीद पर पुरस्कार। ....वास्तव में सरकार समर्थन मूल्य तो तय करती है, पर उस पर खरीद करना ही नहीं चाहती। खरीद करे भी कैसे, बजट/राशि तो हो। जब यह स्थिति है तो हमें अपना उत्पादन बेचने के लिऐ जद्दोजहद तो करनी ही पड़ेगी।

गाँधी जी कहते थे गांव समृद्ध हुए बिना, देश समृद्ध नहीं होगा। आज सरकार शहरों को ही और समृद्ध करने में जुटी है। स्मॉर्ट सिटी के लिए बजट, तो स्मॉर्ट विलेज के लिए, गांव की संरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर), विकास के लिए बजट क्यों नहीं। बिजली, पानी, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा में गांवों के साथ भेदभाव क्यों। क्या गांव के लोगों को दोयम दर्जे का समझा जाता है। गांव – किसान का बजट शहर के बराबर क्यों नहीं ?? भेदभाव क्यों, ऐसे में गांवों की समृद्धता की कल्पना बेमानी है। गांधी जी के शताब्दी वर्ष में सरकार उनके संदेश को तबज्जो दे और इस दिशा में सोचे, यही हमारी मांग है, आग्रह है।

सरकार की नीतियां, आयात–निर्यात का निर्णय विश्व व्यापार संगठन के दबाव पर निर्भर है, सरकार उससे उबर नहीं पा रही है। इसके चलते किसानों का कभी भला होने वाला नहीं है। आगामी सालों में सरकार की नीति खेती के रकबे व किसानों की संख्या को आधा करने की है, उद्योगों को सहयोग करने के चलते सरकार हमें शहरों में दिहाड़ी मजदूर बनाने कार्यरत है। केंद्र सरकार कहती है संघीय ढांचे में – कृषि, सिंचाई, बिजली प्रान्तों का विषय है, प्रान्त बोलता है केंद्र का नियंत्रण है, सहयोग का अभाव है, हम दो पाटों के बीच पिस रहे हैं। नीचे स्तर पर भ्रष्टाचार चरम सीमा में व्याप्त है, डिलीवरी सिस्टम चरमराया हुआ है, सहकारी समितियाँ जो सीधे किसानों को सेवाएं, सुविधाएं देने के लिऐ जिम्मेदार है, जमीन पर डिलीवर करने में बिलकुल भी सक्षम नहीं है, इनको सूद्रढ़ करने कोई ठोस प्रयास कभी नहीं हुऐ।

किसानों को खेती के अतिरिक्त अन्य धंधों से जोड़े बिना उनकी आर्थिक उन्नति असंभव है। उनके उत्पाद की प्रोसेसिंग से लाभ कमाने के अवसर उन्हें मिलने चाहिऐ। हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक जिन पर हमने भरोसा जताया है को आगे आकर हमारी आवाज उठानी होगी, हमारे लिए लड़ना होगा। हम सबको मिलकर उन्हें हमारा साथ देने, बाध्य करना होगा।

हम यह अच्छी तरह समझ लें कि 'खेती और किसान' घोर संकट में हैं। अब समय आ गया है, हमे सचेत होना होगा। हम सबको मिलकर, सारे मतभेद भुला कर, एक होकर अपने हकों व हितों के लिये संघर्ष हेतु तैयार होना होगा।

40 वर्षों से किसानों के बीच काम करने के अपने अनुभवों के आधार पर अब हमें खुलकर कहना पड़ रहा है कि, हम किसानों के संगठनों ने ज्यादातर अपने–अपने स्वार्थों, और अपने अहम की ही पूर्ति की है। संगठनों का उपयोग तथाकथित लोगों ने अपने लिए ही ज्यादा किया है, और उनके मोहरे, सहायक बने हम।

अपनी–अपनी ढपली, अपना–अपना राग, अपना–अपना स्वार्थ। अहम, अहंकार बस। इन्होंने किसानों को तबकों में बांटने का काम ज्यादा किया है, किसानों को एक सूत्र में बांधने व उनकी संगठित लड़ाई लड़ने का काम कम, और सरकारों का भी इसमें बड़ा योगदान रहा, उनकी 'फूट डालो और राज करो' की नीति/चाल...सफल हुई। ये क्यों चाहेंगे कि किसान एक हो। सरकार व सभी राजनैतिक पार्टियां सारे हथकंडे अपनाने का प्रयास करती है, उन्हें चिंता रहती है 'कहीं किसान एक न हो जाएं'। हमें तोड़ते रहने के भरपूर प्रयास में उनके पाले पोसे एजेंट गांवों में निरंतर सक्रियता से इस काम को अंजाम देते रहते हैं, पर सुखद यह है कि अब किसानों की समझ में आ रहा है। उसका मोह भंग हो गया है, इनसे भरोसा उठ गया है, आस्था टूट रही है। 'एक हुए बिना अब कोई भी 'लड़ाई', और 'बिखरा हुआ संघर्ष' हमें परिणाम नहीं दे पायेगा, यह हमें गंभीरता से समझना होगा। जब सभी संगठनों का एक ही उद्देश्य है, 'किसान खुशहाल हो', तो फिर बाधा किस बात की।

हम सब अपना–अपना अहम, स्वार्थ एक तरफ रखें, थोड़ा त्याग करें और किसानों की सोचें, उनकी भलाई के लिए एक साथ, आएं, सब अपने–अपने झंडे, बैनर छोड़कर, और यदि संभव न हो तो साथ लेकर, बैठें एक साथ, खड़े हों एक साथ, चलें एक साथ, और लड़ाई लड़ें एक साथ। यही अपील है, विनम्र प्रार्थना है।

हमें उम्मीद है, कम से कम नवजवान किसान भाई तो यह बात समझेंगे, अब उनकी ही बारी है, उन्हें ही आगे आना होगा, मोर्चा संभालना होगा, अपने खातिर, अपने बच्चों के खातिर।

---

* गवर्निंग बॉडी सदस्य, भारत कृषक समाज

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

RNI No. 831/1957
पोस्टल रजि० **DL (S)-01/3092/2018-20**
पहले भुगतान किये बिना पोस्ट करने का लाइसेंस नं० **U(C)-92/2018-20**

प्रकाशन की तिथि : 1 जुलाई, 2019
नई दिल्ली पी.एस.ओ, नई दिल्ली–1,
तारीख 4 एवं 5, जुलाई 2019

शोक समाचार

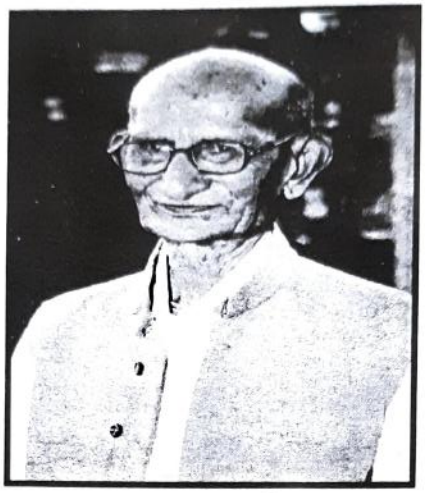

भारत कृषक समाज श्री नाथू लाल जैन जी, गर्विनिंग बॉडी सदस्य, भारत कृषक समाज के 24 मई, 2019 को जयपुर, (राजस्थान) में हुऐ दुःखद निधन पर शोक व्यक्त करता है।

श्री जैन ने 5वीं कक्षा तक पढ़ाई की थी। वह 10 एकड़ भूमि (सिंचित खेत) के मालिक थे। वह बहुत ही प्रगतिशील और उत्सुक कृषक थे, उन्होंने कृषि, पौधों, पोषक तत्वों और नई बीज किस्मों के संतुलित उपयोग के साथ गेहूं, चना, सरसों, बाजरा, मूंगफली और कुछ अन्य फसलों को उगाने के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाया था।

वह भारत कृषक समाज के बहुत ही सक्रिय सदस्य थे, वह कृषक समुदाय के एक समर्पित संगठनकर्ता थे और अपने साथी किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिऐ एक मार्गदर्शक और सलाह प्रदान करने के लिऐ हमेशा उपलब्ध रहते थे। श्री जैन सहकारिता के विकास से भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कृषि क्षेत्र में सर्वांगीण प्रगति के लिए सहकारिता आंदोलन बहुत आवश्यक है।

हम प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति मिले तथा दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो।

O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O

भारत कृषक समाज ए–1, निजामुद्दीन वेस्ट, नई दिल्ली– 110013, फोनः 011–24359509, 9667673186, ई–मेलः ho@bks.org.in, वैबसाईटः www.farmersforum.in के लिए श्री उरविन्द्र सिंह भाटिया द्वारा सम्पादित, मुद्रित व प्रकाशित तथा एवरेस्ट प्रेस, ई 49/8 ओखला इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेस –2, नई दिल्ली –110020 द्वारा मुद्रित।